भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2051

दिनांक 10 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को जलवायु-अनुकूल बनाना

2051 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उच्च जोखिम वाले जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बैकअप बिजली, जल सुरक्षा, शीतलन प्रणाली और बाढ़-रोधी डिजाइन जैसी जलवायु-अनुकूल विशिष्टताओं को अनिवार्य बनाने के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) में संशोधन करने का विचार रखती है;

(ख) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीसीएचएच) के अंतर्गत मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना की जलवायु- अनुकूलन क्षमता में कमियों का कोई आकलन किया गया है; और

(ग) क्या चरम मौसम की घटनाओं के दौरान अवसंरचना की अनुकूलता और सेवा निरंतरता पर नज़र रखने के लिए एक वास्तविक समय निगरानी तंत्र स्थापित किए जाने पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस), जिसकी अनुशंसा 2022 में की गई थी, अवसंरचना और सेवा प्रदायगी संबंधी मानदंडों के अनुसार जलवायु अनुकूलन और पर्यावरण की दृष्टि से धारण योग्य घटकों को शामिल करता है। इनमें विश्वसनीय बिजली बैकअप प्रणाली, जल सुरक्षा उपाय, पर्याप्त शीतलन और वातायन व्यवस्था, और बाढ़ से बचाव और आपदा की तैयारी के लिए संरचनात्मक अवधारणा शामिल हैं। संशोधित दिशानिर्देशों का मूल्यांकन इस लिंक के माध्यम से किया जा सकता है:

https://nhm.gov.in/images/pdf/guidelines/iphs/iphs-revised-guidlines-2022/03_PHC_IPHS_Guidelines-2022.pdf

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनपीसीसीएचएच) के अंतर्गत, हरित और जलवायु अनुकूलन (जीसीआर) स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्र आकलन टूल नामक एक संरचित मूल्यांकन ढांचा विकसित किया गया है। यह टूल जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का व्यवस्थित मूल्यांकन करके जलवायु अनुकूलन और पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित कमियों एवं अवसरों की पहचान करने में सक्षम बनाता है। इसमें ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्मार्ट एवं ग्रीन बिल्डिंग तथा जलवायु अनुकूलन उपायों जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। यह टूल निम्नलिखित लिंक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है:-

https://ncdc.mohfw.gov.in/centre-for-environmental-occupational-health-climate-change-health/

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लयू) सभी राज्यों में एक समान, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आईपीएचएस 2022 दिशानिर्देशों को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है। आईपीएचएस का कार्यान्वयन राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी में सुधार और सभी नागरिकों को आवश्यक न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अंतर्गत एक ओपन-सोर्स टूलकिट (ओडीके) और एक डैशबोर्ड शुरू किया है, जो राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुपालन की त्वरित निगरानी करने और तदनुसार कार्रवाई करने में सहायता करेगा।

******